महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन

(AIBEA ला संलग्न)

दादीशेठ हाऊस, कावासजी पटेल स्ट्रीट, अकबर अलीज समोर, पहिला मजला, फोर्ट, मुंबई - ४०० ०२३.

फोन नं. : २२८८६१८७ / २२८७२५१९ e-mail : msbef@gmail.com / msbef1947@gmail.com

सर्व संलग्न युनिटकरिता
कॉम्रेड्स,

दिनांक : 27 जानेवारी 2022

जागे रहा, क्रियाशील रहा !

आपणास माहित आहेच कि लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी रोजी सुरू होत आहे. दिनांक 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री वर्ष 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडतील. या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 11 फेब्रुवारी रोजी संपत

(मराठी में परिपत्र का अंग्रेजी अनुवाद)

महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ
(एआईबीईए से संबद्ध)

दिनांक: 27 जनवरी 2022
सभी संबद्ध इकाइयों को

साथियों,

सतर्क रहें, सक्रिय रहें!

जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री साल 2022-23 का बजट पेश करेंगी। सत्र का पहला चरण 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में 14 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को खत्म होगा। इस बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. यह देखते हुए कि इस

राज्य ने हमेशा भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाई है, सभी राजनीतिक दलों की नजर इस चुनाव पर है।

ज्वालामुखी के मुहाने पर है देश!

आसन्न चुनाव, किसानों के दबाव, उनके असंतोष और पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों पर उनके प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है। इन चुनावों को ध्यान में रखकर बजट तय किया जाएगा और मतदाताओं को गुमराह किया जाएगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मतदाता सरकार के झूठ का जवाब कैसे देते हैं। इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ रही है। रोजगार सृजित करना भूल जाइए, लोगों को उनकी मौजूदा नौकरियों से भी वंचित कर दिया गया है। गरीबी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई तेजी से बढ़ रही है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन ऑक्सफैम ने हाल ही में असमानता के खतरों की सूचना दी है। हालांकि सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया है, लेकिन किसान असंतुष्ट हैं क्योंकि उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पूरी नहीं हुई है। श्रम कानूनों और मुद्रीकरण, निजीकरण, अप्रतिबंधित संविदाकरण और आउटसोर्सिंग ने श्रमिकों में असंतोष बढ़ा दिया है। GST टैक्स, Amazon, Flipkart, Reliance, D-Mart, More, आदि ने छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को नष्ट कर दिया है। छोटे और मझोले निर्माताओं को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा है। बाजार में माल की मांग नहीं होने के कारण फैक्ट्रियां नीचे जा रही हैं, जिससे सरकार का कर संग्रह भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए, मौजूदा नौकरियां सिकुड़ रही हैं। आम आदमी की क्रय शक्ति में और गिरावट आ रही है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अमीरों के करों में वृद्धि करनी होगी। अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तो भी सरकार को विभिन्न माध्यमों से धन के इनपुट को सुनिश्चित करना होगा और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना होगा। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महंगाई न हो। अर्थव्यवस्था का गंभीर संकट असंतोष और विद्रोह को जन्म दे रहा है। देश एक ज्वालामुखी के मुहाने पर है।

28-29 मार्च की हड़ताल को सफल बनाएं!

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, सरकार ने बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2021 पेश करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिसे बजट सत्र में पारित किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में उनके बहुमत को देखते हुए यह आसानी से संभव है। इस मामले को लेकर एक विरोधाभासी खबर आ रही है। जिस वर्ग के हित निजीकरण में शामिल हैं, वह सरकार को बिल पास कराने के लिए मजबूर जरूर करेगा। निजी हितों का देश, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था या लोगों से कोई लेना-देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमें 28 और 29 मार्च की हड़ताल को सफल बनाना है. हड़ताल के माध्यम से हमें बैंकों के निजीकरण का कड़ा विरोध करना चाहिए। हमें अपने संघर्ष में पूरे मजदूर आंदोलन और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर सरकार ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश करने की हिम्मत की, तो हमें सड़कों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

एक मजबूत प्रतिरोध बनाएँ!

इन चुनौतियों का सामना करते हुए, हमें तीसरे कोरोनावायरस लहर के खिलाफ सावधानी बरतते हुए कार्रवाई की योजना बनानी चाहिए। सभी संबद्ध संगठन एवं जिला समितियां अपने सदस्यों के साथ ऑनलाइन बैठकें आयोजित करें। सदस्यों को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया जाना चाहिए और इस कठिन समय में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें अपने बैंक, ग्राहकों, समुदायों, समाजों, स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों और संगठनों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई में शामिल करना चाहिए। समाज के सभी सदस्य, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, व्यापारी, व्यवसायी, किसान,

श्रमिक, कृषि श्रमिक, चाहे संगठित हों या असंगठित, हमारे अभियान में शामिल होने चाहिए, जो हमें एक मजबूत प्रतिरोध बनाने में सक्षम बनाएगा।

"अब कोई नारा न होगा, सिर्फ देश बचाना होगा"

मजदूरों के आंदोलन के मामले में बैंक कर्मचारी आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अस्तित्व और इस तरह हमारा अस्तित्व इस संघर्ष पर निर्भर है। साथ साथ यह संघर्ष देश के करोड़ों लोगों और उनकी 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। । इसलिए हमारा एक ही आह्वान है "अब नारा होगा, देश को बचाना होगा"। हमें उम्मीद है कि हम सभी इस समयबद्ध कॉल का अच्छी तरह से जवाब देंगे। इस अभियान की सफलता के लिए प्रयास करने की विनम्र अपील है।